ग्रामीण आवास योजना

*77. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण आवास परियोजना के लिए कोष स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी सरकार 1985-86 से इन्दिरा आवास योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और मुक्त बंधवा मजदूरों को निःशुल्क मकान प्रदान करता है। वर्ष 1993-94 से इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया है लेकिन शर्त यह है कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाला लाभ कुल आवंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 1995-96 से इस योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए सशस्त्र सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों के सैनिकों के परिवारों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इन्दिरा आवास योजना एक लोकप्रिय कार्यक्रम साबित हुआ है। और इसके शुरू होने से लेकर अब तक लगभग प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक मकानों का निर्माण हुआ है। 1985-86 से 1994-95 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 20,19,010 मकानों का निर्माण किया गया है जिन पर 2434.73 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष-वार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	व्यय (रुपये करोड़ में)
1985-86	51252	57.93
1986-87	160197	149.10
1987-88	169302	235.37
1988-89	139192	149.65
1989-90	186023	188.50
1990-91	181800	213.07
1991-92	207299	263.01
1992-93	192585	138.83
1993-94	360047	464.04
1994-95	371313	475.15
योग	2019010	2434.73

सारे देश में इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए और इस तथ्य के कारण भी, कि प्रत्येक वर्ष आवासहीन परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशियों का आवंटन 1994-95 में 438 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1995-96 के लिए 1250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। (राज्यों का अंश सहित) और 10 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी, 1996 तक 4.93 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है।

Setting up of bio-fertilizer plants in Gujarat

*78. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have allowed the Krishak Bharati Cooperative Ltd. (KRIBHCO) to set up two bio-fertilizer plants in the cooperative sector in Gujarat;

(b) if so, the details thereof alongwith their locations and the estimated expenditure likely to be incurred thereon;

(c) whether any Gujarat State agency is proposed to be associated with the projects; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) and (b) KRIBHCO has set up a bio-fertilizer